चारी नि:शुल्क राशन अथवा यदि प्रशासनिक कारणों से नि:शुल्क राशन जारी न किया जा सका हो तो उसके बदले राशन का पैसा पाने के पात्र नही थे ।

स्थतिक सरचनाओं और यूनिटो में जिनमें सैनिक फार्म भी शामिल हैं, कार्य कर रहे कार्मिक नियमानुसार फील्ड सर्विस रियायते पाने के पात्र नही थे । इस प्रकार से ऐसे फार्मों के असैनिक कर्मचारी नि:शुल्क राशन अथवा उसके बदले राशन का पैसा पाने के पात्र नही थे । तथापि, छम्ब मे विशेष स्थिति तथा वहा रहने की कठिन परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए ऐसे कार्मिको के लिए अपवाद किया गया था । सरकार ने इस आशय की कोई घोषणा नही की है कि अन्य सैनिक फार्मों के कर्मचारियों को नि:शुल्क राशन अथवा उसके बजाए राशन का पैसा दिया जाएगा ।

Malaysian Government request for Indian Engineers

1573. SHRI DHARAMARO AFZALPURKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Malaysian Government have requested India to help it by providing Engineers to prevent delay in development projects; and

(b) if so, the gist thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) No such request has been made.

(b) Question does not arise

Cases of corruption in 1971-72 investigated by Director of Vigilance

1574 SHRI DHARAMRAO AFZALPURKAR: Will the Minister of SUPPLY be pleased to state:

(a) the number of cases of corruption detected, investigated and disposed of during the year 1971-72 by the Director of Vigilance of Department of Supply; and

(b) the action taken as a result thereof against the persons involved?

THE MINISTER OF SUPPLY (SHRI SHAHNAWAZ KHAN):

(a)	(i) No. of cases de ected and investigated	54
	(ii) (a) No. of cases disposed of during 1971-72	24
	(b) No. of cases disposed of subsequently	18
	(c) Cases still under investigation	12
(b)	(i) No. of officers warned	3
	(ii) No. of officers in whose cases assignment changed	2
	(iii) No. of officers censured.	1

परमिटों के द्वारा लोहे और इस्पात की उचित मूल्यों पर सप्लाई

1575. श्री मुल्की राज सैनी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर लोहा देने की क्या व्यवस्था है ;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इस्पात के मूल्य कितने कितने प्रतिशत बढ़ें; और

(ग) क्या सरकार का विचार परमिट जारी करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु प्रबन्ध करने का है ?